भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2404

06 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए नियत

हाइब्रिड वाहन

2404. श्री सी. एम. रमेश:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित करने की तुलना में हाइब्रिड वाहन अधिक व्यावहारिक मध्यावधि समाधान हैं;

(ख) यदि हां, तो फेम-II के अंतर्गत प्रोत्साहन दिए जाने को बंद करने के हाल के निर्णय पर मंत्रालय का दृष्टिकोण क्या है;

(ग) क्या इलेक्ट्रिक वाहनों में व्हील-टू-व्हील कार्बन उत्सर्जन 158 ग्राम/किमी है, जबकि हाइब्रिड वाहनों में यह 133 ग्राम/किमी है;

(घ) पेट्रोल और डीजल वाहनों के व्हील-टू-व्हील कार्बन उत्सर्जन का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्सर्जन की गणना करते समय केवल विद्युत उत्पादन उत्सर्जन को ध्यान में रखती है, कोयला उत्पादन उत्सर्जन को नहीं; और

(च) सरकार द्वारा मध्यावधि समाधान के रूप में हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (च): भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण और उनके अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने और वाहनों के उत्सर्जन के मुद्दों का निवारण करने के उद्देश्य से 2015 में अखिल भारतीय आधार पर भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फ़ेम इंडिया) स्कीम शुरू की। इसके अतिरिक्त, फेम इंडिया स्कीम का चरण-I। कुल 11,500 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से 01 अप्रैल, 2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया है। फ़ेम-II के अंतर्गत हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपभोक्ताओं (खरीदारों/अंत-प्रयोक्ताओं) को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

(ख): फेम इंडिया स्कीम, चरण-II 31.03.2024 को समाप्त हो गया है।

(ग), (घ) और (ङ): इस मंत्रालय ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है।

*****